to send their specific comments. However, the Ministry is already supporting urban Basic service projects and also assistaing State Government through a scheme for the development of small & medium towns. The Ministry is also taking various steps to improve the capability of municipal personnel in order to executing various projects and is assisting three Regional Centres at Bombay, Lucknow and Hyderabad in addition to the IIPA in New Delhi by providing grant / assistance. Besides, training courses are run by the Regional Centres and National Institute of Urban Affairs for personnel of UBS projects under the schemes for training are taken up under world Bank assisted projects. the training Institute under HUDCO runs courses for housing and urban services.

मध्य प्रदेश को सूखा राहत

1886 **श्री कपिल वर्मा:**
श्रीमती वीणा वर्मा:
श्री सुशील बरोंगपा:

क्या **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के रायपुर एवं रीवा संभागों के सूखा प्रभावित जिलों में विद्यमान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के लिए मदवार कितनी-कितनी राशि की मांग राज्य सरकार द्वारा की गई है;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने, पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने, न्यूट्रिशन कार्यक्रम, पशु चारे स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिए अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि की मांग की गयी है;

(ग) मांगी गई राशि के मुकाबले उक्त दोनों वर्षों के लिए विभिन्न मदों में किस-किस प्रयोजन के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी थी,

(घ) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत दी गयी राशि के अलावा अब तक कितनी-कितनी राशि दी जा चुकी है, और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राहत कार्यों में लगे मजदूरों को मजदूरी के एक भाग के रूप में अनाज देने हेतु विशेष सहायता के रूप में अनाज आवंटित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव): (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने ज्ञापनों में रायपुर और रीवा डिवीजनों के जिलों में सूखा-राहत के लिये वर्ष 1988-89 और 1989-90 के लिए मांगी गई सहायता की मदवार सूचना विवरण में दी गई है [नीचे देखिये]

(ग) और (घ) प्रभावित क्षेत्रों में सूखा राहत उपाय करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को अर्थोपाय पेशगी के रूप में 10 करोड़ रुपये की एक रकम दी जा चुकी है।

(ङ) राज्य सरकार ने राहत कार्यों में लगे कार्यकर्ताओं में वितरण के लिए एक लाख मीटरी टन अनाज विशेष सहायता के रूप में प्राप्त करने के लिये अनुरोध किया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थापित कार्यपद्धति के अनुसार विचार किया जा रहा है।

विवरण

सूखा राहत के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई मदवार सहायता

क्र० सं०	मद	मांगी गई सहायता		कुल
		1988-89 (नवम्बर, 88 से मार्च, 1989 तक)	1989-90 (अप्रैल से जून 1990 तक)	
1	रोजगार सृजन	2533.01	2029 50	4562.51
2.	आदानों पर राजसहायता	359 46	721.22	1080.68
3.	पीने के पानी का अभाव जिसमें पानी की ढुलाई भी शामिल है	322.10	820.30	1142.40
4	पोषण	429.44	301.17	730.61
5.	जन स्वास्थ्य	286.29	280.87	567.16
6.	अनुग्रह राहत	9.70	9.70	19.40
7.	चारा अभाव और पशु स्वास्थ्य	215.30	457.00	672.30
8	सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना	28.30	—	28.30
	कुल :	4183.60	4619.76	8803.36

funds for poverty alleviation programme

1887 SHRI K V. THANGKABALU: Will the Minister of Agriculture be pleased to state

(a) the funds made available to the States, State-wise, under the poverty alleviation programmes from April, 1988 till 31st December, 1988;

(b) the funds utilised in each State during this period, and

(c) the number of persons brought above the poverty line during this period, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHAN POOJARI) :(a) and (b) Information regarding funds made available and utilised under the poverty alleviation programmes of IRDP, NREP and RLEGP is enclosed in the annexure [*See* Appendix CXLIX, Annexure No 106]

(c) Under IRDP, persons below poverty line are sanctioned loan and subsidy for income generated assets. Crossing of poverty line is a continous process and impact of the programme is achieved over a period of time only. As regards NREP and RLEGP, only employment is generated on various works and people are given wages for the work. Crossing the poverty line is not monitored under these two employment programmes.